

**PRESIDENT'S ADDRESS LAID ON
THE TABLE**

SECRETARY-GENERAL : Sir, I beg to lay on the Table a copy (in Hindi and English) of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 21st February, 1994. (Placed in library. See No. L.T. 5318/94).

*[Text of the Address delivered by the
President (Dr. Shanker Dayal Sharma
in Hindi]*

माननीय अध्यक्ष,

असह्य के इस अधिवेशन में आपको स्वागत करता हूँ।

सत्र वर्ष में आपको संबोधित करते हुए मुझे यह महसूस हो रहा है कि आज देश का परिपेक्ष्य विगत वर्ष की तुलना में बदला हुआ है। वर्ष 1993 के शुरू में हमारे सामने अनेक कठिनाइयाँ आईं, लेकिन जैसे-जैसे सत्र वर्ष बीता गया, हमारे नागरिकों व अन्यधिक स्वस्थ प्रतिष्ठिता अनेक और 1993 का वर्ष समाप्त होते-होते निश्चित ही आशा की किरण सामने दिखाई देने लगी। सभी मोर्चों पर निरंतर प्रगति हुई, जिसका आभास कानून तथा व्यवस्था की सुधरती हुई स्थिति, खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन, खरीद के अभूतपूर्व स्तर, डायाग्रों के बहुत बड़े भंडार, मुद्रास्फीति को एकल अंकीय स्तर पर बनाये रखने, विदेशी मुद्रा के संतोषजनक भंडार, व्यापारिक घाटे में पर्याप्त कमी, निर्यात में वृद्धि, मूलभूत संरचना के कुछ आवश्यक क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार और प्रत्यक्ष तथा पोर्टफोलियो, दोनों में अधिक विदेशी पूंजी निवेश से मिलता है। ये सभी हमारे उभरते हुए आशावाद के प्रतीक हैं, और इसके औचित्य को सिद्ध करते हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ऊर्जा को और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपने विश्वास को फिर से प्राप्त कर लिया है। हमारे पास इस सर्वतोमुखी उपलब्धि पर संतुष्टि

महसूस करने का कारण है, और इसका प्रमाण है। लेकिन हमने अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। इसी आशा के आधार पर सरकार 1994 में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है।

कानून और व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार आया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह की स्थिति नियंत्रण में रही। पिछले वर्ष पंजाब में जो सफलता प्राप्त हुई, उसे और सुदृढ़ किया गया है। देश के पांच राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। सरकार इस सुधार की उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प है, और शेष महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयासरत है।

पिछले वर्ष लगभग इसी समय राष्ट्रीय परिदृश्य पर अयोध्या मसले की छाया रही। विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों के संभावित असर को लेकर लोगों में गहरी चिंता व्याप्त थी। देशवासियों में व्याप्त बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को ही यह श्रेय प्राप्त है कि तरह-तरह की जो आतियाँ फैलाई जा रही थीं, वे सब गलत साबित हुईं। वातावरण में पर्याप्त सुधार आया है, और हम इस विवाद के स्थायी समाधान की आशा कर सकते हैं। संविधान के अंतर्गत यह मामला उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है, और इस न्यायालय द्वारा उस पर कार्यवाही की जा रही है। उच्चतम न्यायालय की राय को ध्यान में रखते हुए, सरकार समुचित उपाय करेगी।

अयोध्या का मसला आज साम्प्रदायिकता को राजनीति से जोड़ने में निहित खतरे का ज्वलंत उदाहरण है। इस विकार को दूर करना और धर्म तथा राजनीति; दोनों को अपने-अपने न्यायसंगत क्षेत्रों में बनाए रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म निरपेक्ष देश की आज यही मांग है। आवश्यकता इस बात की है कि इस मसले पर पूरी तरह से विचार-विमर्श किया जाए, और इसके लिए कारगर उपाय

किए जायें। सरकार इस बारे में दिए गए सुझावों का स्वागत करेगी।

जम्मू और कश्मीर में हम आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने की नीति पर बल रहे हैं। इस वर्ष पुलिस तथा सुरक्षा सेनाओं को अपनी आतंक-विरोधी कार्रवाइयों में पर्याप्त सफलता मिली है। इनकी कार्य-क्षमता को और बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। इस बात के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बल प्रयोग करने में अधिक से अधिक संयम बरता जाए। अक्षरतबल दरगाह में जो भारी संकट उत्पन्न हो गया था, उसे प्रशासन और सुरक्षा सेनाओं ने जनता के सहयोग से सराहनीय ढंग से हल किया। इस संकट के समाधान ने सरकार के संयम के दृष्टिकोण की क्षमता को प्रदर्शित किया है। जब भी कोई ऐसी घटना हुई है, जिसमें लगा हो कि बल का अधिक प्रयोग किया गया है, तो तुरन्त जांच बैठायी गई है, और इस पर कार्रवाई की गई है। कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है, साथ ही प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे हैं। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया गया है, और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। हम आम जनता की परेशानियों के बारे में बहुत चिंतित हैं। हम जनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी प्रभावी भागीदारी का भी प्रयत्न कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर, भारत का अविभाज्य अंग है, और हम इसमें सीमा पार से या अन्य किसी ओर से अस्थिरता पैदा करने के किसी भी प्रयास को निष्फल कर देंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ो समझौते के अनुरूप अंतरिम बोडोलैंड स्वायत्त परिषद की स्थापना जनजातीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। जब कोकराझार और बोंगाई-गांव जिलों में गैर-जनजातीय लोगों के खिलाफ हिंसा भड़की, तो असम सरकार

ने त्वरित कार्रवाई की। नागा और कुकी लोगों के बीच हिंसा भड़कने और मणिपुर में कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति बिगड़ने पर सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्रवाई की। इससे यह परिलक्षित होता है कि सरकार विघटनकारी तत्वों से सख्ती से निपटेगी।

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। आयोग के सदस्यों में एक भूतपूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के और एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के हैं। आयोग की स्थापना इस बात की द्योतक है कि हम मानवाधिकार के मामले पर गंभीर और स्पष्ट कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। आयोग ने पूरे संकल्प से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाब-देही को सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल, 1993 में विभागों से संबद्ध संसद की 17 स्थायी समितियां गठित की गईं, ताकि संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों, अनुदान मांगों, मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों और राष्ट्रीय बनियादी दीर्घकालीन नीति प्रलेखों की विस्तृत जांच की जा सके। इससे संसद के कामकाज में भारी सुविधा होगी।

देश को प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र में भूकंप से हुई अभूतपूर्व क्षति इनमें सबसे बड़ी है। इन सभी आपदाओं में सरकार ने सराहनीय सतर्कता का परिचय दिया है, और तेजी से राहत प्रदान की है। कई अन्य देशों की सरकारों, विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं ने भी तत्परता से सहायता की है। हम उन सभी के आभारी हैं। महाराष्ट्र के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में एक हजार करोड़ रुपए के परिष्कृत का एक बृहद पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस पुनर्निर्माण कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों को भी समुचित रूप से संबद्ध किया जा रहा है।

1991 यमें शुभ किए गए आर्थिक सुधारों ने पिछले वर्ष गति पकड़ी और उन्हें निरन्तर आगे बढ़ाया गया है। इसके बावजूद अभी और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। सरकार यह जानती है कि सुधार कभी भी पीछे न मुड़ने वाली और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके प्रति देश की प्रतिक्रियाओं तथा परिस्थितियों को हमेशा ध्यान में रखकर दृढ़ता और दूरदर्शिता से इसे लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप कार्यक्रमबन्धन में निरन्तर और ठोस प्रगति हुई है, जो आम सहमति पर आधारित है। हम सावधानी से इस गति को और आगे बढ़ायेंगे।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के कार्य निष्पादन तथा उनकी भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कमी की गई है, तथा कुछ और उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। 31 मार्च, 1993 को घोषित नई आयात-निर्यात नीति में कृषि और सेवाओं के क्षेत्र, जिनमें देश तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर स्थिति में है, निर्यात की प्रक्रियाओं को कारगर और उदार बनाने के प्रयास किए गए। वर्ष 1993-94 के बजट में अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की सुविधा प्रदान की गई।

सुधार कार्यक्रम तैयार करते समय सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधारों पर विशेष बल दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं को अनिवार्यतः नया स्वरूप देना और उन्हें मजबूत बनाना होगा, ताकि वे निजी क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधियों के कारण आए नये उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकें। मार्च, 1993 में एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन विनिमय दर का एकीकरण और रुपए को खुले बाजार में प्रवाह की छूट प्रदान करना था। यह तथ्य कि रुपए को खुले बाजार में लाने के बाद उसका मूल्य स्थिर रहा है, इस विषय में सरकार के उचित निर्णय का प्रमाण है।

मूल आर्थिक सूचकों से यह पता चलता है कि हालांकि यह वर्ष कठिन परिस्थितियों में प्रारम्भ हुआ था, किन्तु वर्ष 1993-94 के दौरान अर्थव्यवस्था का कार्य निष्पादन संतोषप्रद रहा है। वर्ष 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानतः 4% की वृद्धि हुई है। सरकार को यह आशा है कि वर्ष 1993-94 में भी विकास की दर लगभग इसी स्तर पर बनी रहेगी। इस वर्ष कुछ समय के लिए मुद्रास्फीति की दर गिर कर 6% से भी कम हो गई, जबकि इसकी उच्चतम दर 8.4% रही।

अन्तरराष्ट्रीय निवेशकों का भारतीय बाजार में विश्वास बढ़ा है। नई औद्योगिक नीति के प्रारंभ से 1993 के अंत तक अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश इक्विटी के रूप में अब लगभग 13,000 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में 65,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश होने का अनुमान है। इस पूंजी निवेश की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका अधिकांश भाग बिजली, तेल शोधन, खाद्य प्रसंस्करण, धातुकर्मीय उद्योग, विद्युत उपस्कर, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगाये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित पूंजी निवेश का लगभग 7% ही ऐसे उत्पादों के लिए होगा, जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। निवेश की इस राशि को 3-4 वर्ष की अवधि में खर्च किया जाएगा, जो कि वृहत परियोजनाओं के प्रारंभ होने से उत्पाद शुरू होने तक की अवधि है।

सरकार निर्यात को बढ़ावा देने पर बराबर भारी जोर दे रही है। व्यापार नीति में किए गए परिवर्तनों एवं विनिमय दर को मुक्त किए जाने तथा अर्थव्यवस्था का सामान्य उदारीकरण किए जाने के सुपरिणाम निकले हैं, और निर्यात में खासी वृद्धि हुई है। अप्रैल-दिसम्बर, 1993 की अवधि में यह वृद्धि डालर के रूप में 20% के करीब थी, जबकि 1992

की इसी अवधि में यह वृद्धि 3% से कुछ अधिक थी।

सरकार कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पर्याप्त और तर्क-संगत मूल्यों वाले निवेशों का समय पर प्रावधान करना, तथा एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना, जिससे समय पर मूल्य की घोषणा हो सके, और जिससे अधिक उत्पादन हो, तथा देश की घरेलू जरूरतों के साथ-साथ निर्यात की जरूरतों को पूरा किया जा सके, सरकार के प्रमुख उद्देश्य हैं। समय कार्यनीति के अनुरूप कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए योजना परिव्यय में 26.6% की वृद्धि कर दी गई है। 1992-93 में जहाँ यह 1,050 करोड़ रुपए था, वहाँ 1993-94 में बढ़ाकर इसे 1,330 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 1992-93 में खाद्यान्न का उत्पादन अठारह करोड़ मीट्रिक टन रहा, जो 1991-92 में हुए उत्पादन से 7.1% से भी अधिक था। 1993-94 में खरीफ फसल में खाद्यान्न का उत्पादन 9 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। रबी की फसल भी बहुत अच्छी होने की संभावनाएँ हैं।

सरकार उद्यान-कृषि, जल-और पर्यावरण तिलहन, दालों तथा निर्यात की संभावना वाली अन्य वस्तुओं को महत्व देकर कृषि क्षेत्र के विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। किन्तु ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हमारे अपने उपभोक्ताओं के हितों को कोई नुकसान न पहुँचे। ग्रामीण सहकारिता ऋण प्रणाली तथा विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में किसानों के लिए विपणन, संसाधन एवं अन्य अनिवार्य सेवाओं को पुनः सक्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र की नयी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विस्तार सेवाओं को व्यापक आधार दिया जाएगा, और इसमें स्वैच्छिक संगठनों का भी और अधिक सहयोग लिया जाएगा।

निर्धनता स्तर को घटाने के उपाय के रूप में हमारी कृषि नीति का लक्ष्य

भू और जल संरक्षण की समन्वित नीति तथा कार्बनिक और जैव-उर्वरकों तथा उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे कृषि निवेशों का प्रयोग बढ़ाकर वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा। आठवीं योजना में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय जल-विभाजक विकास परियोजना के लिए 1,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शुष्क भूमि कृषि प्रौद्योगिकी द्वारा लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि को अनाज, चारा, ईंधन और रेशे के सतत उत्पादन के लिए तैयार किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादन प्रणाली में विविधता आएगी तथा अन्ततः जल-विभाजक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय के स्तर और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इस परियोजना में भूमि-युक्त जल की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे परियोजना क्षेत्र में सूखे से बचा जा सकेगा। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में विकसित किए जाने के लिए 2,500 छोटे जल-विभाजक क्षेत्रों की पहचान की गई है, और इन पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

नामसुक्त उर्वरकों की विनिर्माण क्षमता को भी बढ़ाया गया है, और इसमें भी अधिक वृद्धि की योजना बनाई जा रही है। चूंकि देश में उर्वरकों के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे बालू की उपलब्धता सीमित है अतः विदेशों में विशेषकर खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया के देशों में संयुक्त उपकरण स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार भू पोषकों का संतुलित प्रयोग करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती रहेगी, जिससे उत्पादन का स्तर बनाए रखा जा सके।

कृषि नीति के अंग के रूप में, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे खाद्यान्नों को राज्यों में लाने-ले जाने के संबंध में सभी प्रतिबन्धों को हटा दें।

उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने में सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही प्रबल रही है। गरीबों की खर्च-सामर्थ्य को बढ़ाने की दृष्टि से नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य को सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों की तुलना में 500 रुपए प्रति मीट्रिक टन कम रखा

गया है। वर्ष 1992 में योजना के शुरू होने के समय वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्र के अंतर्गत 10 हजार, 580 नई उचित दर की दुकानों खोली जानी सम्भावित थी। इसमें से इन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य की सीमा को पार करते हुए 11,681 नई उचित दर दुकानें खोली जा चुकी हैं। इस योजना के लागू होने के समय से 1,81,296 टन भण्डारण क्षमता वाला स्थान उपलब्ध कराया गया है, या किराये पर लिया गया है। नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मध्यावधि समीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि योजना लागू होने से पूर्व के की तुलना में, करीब 15 लाख मीट्रिक टन अधिक खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध करा दिया गया है। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक नया ग्रामीण आयाम जुड़ा है। खरीद प्रयासों में तेजी लाए जाने से 1 जनवरी, 1994 को केंद्रीय पूल में स्टॉक 2 करोड़ 20 लाख टन तक पहुंच गया, जो अब तक का रिकार्ड स्टॉक है। आवश्यक हुआ तो सरकार इन क्षेत्रों में और अधिक प्रोत्साहन आसानी से देने की स्थिति में है।

सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे महिलायें हों या बच्चे, अल्पसंख्यक हों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग विकास की मुख्य धारा में अलग नहीं रहना चाहिए। 1993-94 में गरीबों के विकास के हर क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की तुलना में अधिक संसाधन जुटाने गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए संशोधित परिव्यय 56% बढ़ गया, जबकि कल्याण मंत्रालय का योजना परिव्यय 820 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 980 करोड़ रुपए कर दिया गया। सर्वाधिक पिछड़े 120 जिलों में जवाहर रोजगार योजना को सुदृढ़ बना दिया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी की प्रति परिवार 1,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया। 1992-93 में शुरू किए गए ग्रामीण कालीयारों के लिए उन्नत औजार किट कार्यक्रम को 1993-94 में 100 और जिलों में शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार

देश के कुल 162 जिलों में 2 लाख 30 हजार ग्रामीण कारीगरों को लाभ पहुंचाया गया है। बुनकरों के कल्याण एवं विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाए गए। इसके अंतर्गत आवास, कार्यस्थल, हथकरघा विकास केंद्र, क्वालिटी ड्राइंग इकाई, दक्षता विकास के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशील पूंजी शामिल है। वर्ष के दौरान 1,372 करोड़ रुपए लगाए गए। हथकरघा विकास केंद्र एवं क्वालिटी ड्राइंग इकाइयों के लिए सन् 1993 के अंत में कार्यक्रम शुरू किए गए, ताकि वर्तमान इकाइयों का विलय और विस्तार करके नई इकाइयां स्थापित की जा सकें। सन् 1993 के लिए 120 केंद्र तथा 20 इकाइयों के लक्ष्य के स्थान पर 213 केंद्र एवं 94 इकाइयों को स्वीकृति दी गई। 25 केंद्र एवं 25 इकाइयों ने काम करना आरम्भ भी कर दिया है।

सरकार ने निर्धनों, विशेषकर, ग्रामीण महिलाओं एवं शहरी युवकों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि में तीन नई योजना बनाई हैं।

देश के 1,752 सर्वाधिक पिछड़े एवं दूरवर्ती इलाकों में, जहां देश के 17 करोड़ गरीब लोग रहते हैं, ग्रामीण बुनकरों के लिए रोजगार आश्वासन योजना लागू की गई है। ताकि उन्हें कृषि के खाली समय में 100 दिन के लिए मुक्तिविवन सहायता रोजगार सुहृदय कराया जा सके। इस प्रकार यह योजना और ऊंचे स्तर तक ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराती रहेगी।

“महिला समृद्धि योजना” ग्रामीण महिलाओं को अपनी कमाई और घरेलू संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने और बरतने में समर्थ बनाएगी। 4 लाख से अधिक महिलायें पहले ही इस योजना के तहत ग्रामीण डाकघरों में अपने खाते खोल चुकी हैं। इस योजना और राष्ट्रीय महिला कोष से ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होगी।

शिक्षित शहरी युवकों को लघु उद्यमों में सतत रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से

एक रोजगार योजना शुरू की गई है। अब तक विभिन्न राज्यों से युवाओं से लगभग एक लाख 95 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 41,275 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है और उन्हें सिफारिश करके बैंकों को भेज दिया गया है। उनमें से लगभग 2,000 आवेदन पत्र मंजूर कर लिए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान इस योजना में 40,000 लाभभोगियों को शामिल किया जाएगा, और वर्ष 1994-95 से प्रति वर्ष 2 लाख, 20 हजार लाभभोगियों को इसमें शामिल करने का विचार है। इस प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कुल 7 लाख लाभभोगियों को इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। इस योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5% और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें महिला लाभों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इन सभी कार्यक्रमों में जागरूकता पैदा करने, और इनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है।

कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने और उनके संबंध में अपेक्षित निदेश और बल देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने प्रधान मंत्री कार्यालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया है। यह विशेष कक्ष कार्यान्वयन विभागों और क्षेत्रीय भ्रमण तथा स्वतंत्र मूल्यांकनों पर आधारित सूचना से फीड-बैक प्राप्त करेगा, ताकि कार्यक्रमों की सभी संभावित रुकावटों को दूर किया जा सके। संबंधित क्षेत्र में इन कार्यक्रमों के समन्वित कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए सचिवों की एक विशेष समिति का भी गठन किया गया है, जो इन तीनों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

संचार सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में और विस्तार किया जाएगा। वधि

1993-94 में, 46,800 पंचायतों को टेलीफोन से जोड़ा जाएगा। 1994-95 के दौरान 72,000 गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजनाओं में विशेष घटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत आवंटन में सन् 1993 में वृद्धि की गई और इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया, ताकि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% या इससे अधिक है, उन क्षेत्रों में आधारीक संरचना के विकास की योजनाओं को इसमें शामिल किया जा सके।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम का पारित होना इस वर्ष की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास के त्वरित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जा रहा है।

सरकार देश के कुछ भागों में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। कानून के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की रक्षा, तथा उनके लिए बने सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। 1992-93 के दौरान लगभग 21 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों और 8 लाख अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रखा से ऊपर आने में सहायता दी गई। 1993-94 के दौरान सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इन परिवारों की संख्या बढ़कर क्रमशः 27 लाख और 9 लाख हो जाने की संभावना है।

जिन क्षेत्रों में जनजातीय महिला साक्षरता बहुत कम है, उनमें इस वर्ष शिक्षा परिसर बनाने की योजना शुरू की गई। अब तक ऐसे 13 परिसरों को मंजूरी दी गई है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ का कारोबार, जो 1991-92 में 22 करोड़

रूप था, 1992-93 में बढ़कर 86 करोड़ रूपए हो गया है। चालू वर्ष में इसके काफी अधिक बढ़ जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय पिछड़े जाति वित्त और विकास नियम ने चालू वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की। 1993 के दौरान इसने 80 करोड़ रूपए के ऋण मंजूर किए, और आगामी वर्ष में इसका प्रस्ताव अपने काम को दुगुना कर देने का है।

भारत सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का चिह्न प्रतीक्षित आरक्षण 8 सितम्बर, 1993 को तब साकार हुआ, जब मौजूदा सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण के आदेश जारी किए। इसके साथ देश के अन्य पिछड़े वर्गों की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आकांक्षा पूरी हुई।

बाबा साहेब आम्बेडकर की रचनाओं के क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाया गया, और हिन्दी, तमिल, गुजराती, प्रत्येक में दो-दो खंड प्रकाशित किए गए। अन्य भाषाओं में भी कार्य की बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। बाबा साहेब के दर्शन में अनुसंधान करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में आठ पीठों की मंजूरी दी गई है।

मौजूदा वक्त्र अधिनियम, 1954 और वक्त्र (संशोधन) अधिनियम, 1984 के स्थान पर अगस्त, 1993 में संसद में एक नया वक्त्र विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ वक्त्र बोर्ड का और अधिक लोकतांत्रिक गठन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें वक्त्र मामलों से संबंधित मसलों का निर्णय करने और वक्त्र की संपत्ति की बेहतर रक्षा और प्रबन्ध के लिए वक्त्र अधिकरण की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम इस वर्ष काम शुरू कर देगा, जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रूपए होगी। इसका स्वरूप तैयार किया जा रहा है।

अपने पिछले अधिभाषण में मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को सन् 1992 में

की गई समीक्षा और उसमें किए गए संशोधनों का उल्लेख किया था। सरकार साक्षरता और पश्च साक्षरता अभियानों और प्राथमिक शिक्षा के प्रति एक नए जिला-विशेष और समुदाय अभिमुख दृष्टिकोण द्वारा समर्थित पूर्ण साक्षरता अभियानों की अभिनव कार्य नीतियों पर आधारित प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है। केरल और पाण्डेचेरी के सभी 18 जिलों ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। 32 जिलों में; जिन्होंने पूर्ण साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न किए हैं; यह सुनिश्चित करने के लिए कि नव-साक्षर लिखना-पढ़ना भूल न जायें, पश्च साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। इस समय 258 जिलों में 238 पूर्ण साक्षरता अभियान चल रहे हैं।

नए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में भागीदारी योजना एवं प्रबंध पर जोर दिया गया है और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर और विकेंद्रीकृत प्रबंध के माध्यम से स्कूलों की प्रभावशीलता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हाल ही में भारत ने विश्व के नौ सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों को "सबके लिए शिक्षा" शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, और इसमें भारत ने तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस सदी के अंत तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस सदी के अंत तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6% तक शिक्षा परिव्यय बढ़ाने के सरकार के निर्णय की घोषणा की। नौवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस निर्णय को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार पृथक-पृथक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करके विकेंद्रीकृत प्रबंध द्वारा सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है।

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकारों के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर में कमी हो रही है। 1981-91 के

दशक में वार्षिक औसत चरघातांकी वृद्धि दर 2.14% थी, जो वर्ष 1992 में घटकर 1.9% रह गयी है। अशोधित जन्म दर, जो 1951-61 में 41.7 प्रति हजार थी, 1992 में घटकर 29 प्रति हजार रह गयी। अशोधित मृत्यु दर, जो 1951-61 में 22.8 थी, वह 1992 में घटकर 10 रह गई है। कुल प्रजनन-दर, जो 1961 में 5.97 थी, 1991 में घटकर 3.6 रह गई। पूरे देश में शिशु मृत्यु दर 1961 में 146 प्रति हजार जीवित शिशु थी। यह 1992 में घटकर 79 रह गई। यद्यपि ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, परंतु जनसंख्या में वृद्धि अभी भी विचलित करने वाली है। सरकार जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी लाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समूचा राष्ट्र एकमत है। इसके लिए राज्य सरकारों, अग्रणी नेताओं, गैर-सरकारी संस्थाओं और समाज के सभी वर्गों की ओर से बहु-आयामी एवं बहु-क्षेत्रीय प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सभी राजनैतिक दलों को इस सम्बन्ध में एकमत होकर लोगों को छोटे परिवार के मानदंड अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक जन आन्दोलन का रूप देना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने हाल ही में गठित की गई जनसंख्या समिति की सिफारिशों का समर्थन किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह भी निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक भावी कार्रवाई के बारे में मुख्य मंत्रियों और विचारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाये। यह कार्य शीघ्र ही किया जायेगा।

विकास प्रक्रिया और पर्यावरण संरक्षण के परस्पर संबंध के प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं। हमारी वन और वन्य-जीवन नीतियों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उसके बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग की आवश्यकता हमारी प्रमुख नदियों की सफाई और

प्रदूषण निवारण कार्यक्रमों में परिलक्षित होती हैं। जैव-विविधता, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते हुए मरुस्थल के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही बहस में भाग लेते समय हमने 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में संसाधनों, प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने के संबंध में उठाये गये मूलभूत मसलों पर ध्यान केन्द्रित किया। सरकार विकास से संबंधित हमारे प्रयासों में हमारी पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर पूरा ध्यान देगी।

अन्तरिक्ष कार्यक्रमों में निरन्तर प्रगति हुई है। यद्यपि हम पोलर सैटेलाइट लांचिंग व्हीकल की उड़ान में असफल रहे हैं, परन्तु इस अनुभव से काफी लाभ मिला है। संग्रह किये गये आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, और इससे जटिल प्रणालियों की प्रभावशीलता सिद्ध हुई है। पोलर सैटेलाइट लांचिंग व्हीकल की अगली उड़ान अगस्त-सितम्बर, 1994 में किये जाने की योजना बनाई गई है। भारतीय पोलर सैटेलाइट लांचिंग व्हीकल के विकास में भी प्रगति हुई है, जिससे आज से कुछ वर्षों के बाद इनसैट श्रेणी के उपग्रह छोड़े जा सकेंगे। इनसैट-2ए को चालू करने के एक वर्ष के भीतर पिछले वर्ष हमने इनसैट-2बी को सफलतापूर्वक छोड़कर और चालू कर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इनसैट-2बी से दूरदर्शन को अपने पांच उपग्रह चैनल शुरू करके अपनी सेवाओं में वृद्धि करने में मदद मिली है। इससे दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण संभव बना है।

भारत की एक सशक्त और व्यापक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक आधार-संरचना है। भारत ने विभिन्न उच्च-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस संदर्भ में मैं आश्चर्य नहीं हूँ कि पिछले शनिवार को 'ग्रिन्' के प्रक्षेपण में जिस उच्च तकनीकी क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है, उसकी प्रशंसा करने में माननीय सदस्यगण मेरा साथ देंगे। प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की गति और पर्यावरण के अनुरूप प्रौद्योगिकी के प्रयोग की आवश्यकता के

कारण हमसे अपेक्षाएँ काफी बढ़ गई हैं। प्रौद्योगिकी अंतरण पर लंगोये गये प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप हमें अपनी क्षमताओं पर और अधिक निर्भर रहना होगा। सरकार इसके लिये देश में उपलब्ध प्रतिभा की महान क्षमताओं के उपयोग के लिये हर प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिये दृढ़-संकल्प है। उभरते हुए आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अनुसंधान परिणामों से हमारे उद्योग लाभ उठा सकेंगे। उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जायेगा। सूचना प्रौद्योगिकी और आनुवांशिक इंजीनियरी और जैव-प्रौद्योगिकी पर बल दिया जायेगा। सौर एवं अन्य गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग के लिये उन्नत सामग्री और साधनों को भी प्राथमिकता दी जायेगी।

हमारी सशस्त्र सेनायें देश की भूभागीय अखंडता की रक्षा के लिए सीमा पर निरंतर चौकसी रखती हैं। राष्ट्र को इन सेनाओं पर और उन रक्षा वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों पर गर्व है जिन्होंने हमारी रक्षा तैयारियों में सराहनीय योगदान दिया है। गोला-बारूदों के स्वदेशी विकास और रक्षा उत्पादन यूनिटों के विविधीकरण में भी तेजी से प्रगति हुई है।

अपने सामान्य कर्तव्य के अतिरिक्त सशस्त्र सेनायें आवश्यकता पड़ने पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा विद्रोही गतिविधियों से निपटने में सिविल प्राधिकारियों को सहयोग देती रही हैं। वे प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत कार्यों में भी सहायता करती रही हैं। इन क्षेत्रों में इनका कार्य अनुकरणीय रहा है। सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र सेना कर्मियों को बेहतर सुविधाएँ और स्थितियाँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही हैं। फील्ड एरिया में तैनात कर्मियों को हाल ही में अपेक्षाकृत अधिक भत्ते प्रदान किये गये हैं। यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन में एक बार वृद्धि स्कीम का लाभ दो लाख अतिरिक्त पेंशनरों को भी दिया जायेगा।

सतत अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के परिणामस्वरूप सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में यह विश्वास उत्पन्न करने में सफल रही है कि भारत विश्व के सर्वाधिक सुरक्षित पर्यटन स्थलों में से है। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर, 1993 और जनवरी, 1994 के महीनों में पर्यटकों के आगमन में अब तक की रिकार्ड वृद्धि हुई है। यह 1992 और 1993 की इसी अवधि के दौरान आये पर्यटकों की तुलना में क्रमशः 23.8% और 28.4% अधिक है।

पिछले एक वर्ष में सरकार की विदेश नीति हमारे अपने राजनीतिक एवं सुरक्षा हितों के संवर्धन को जारी रखते हुए विदेशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों में हमारे आर्थिक हितों की रक्षा पर केन्द्रित रही। हमारे आर्थिक सुधारों की सार्थकता में विदेशों को प्रभावपूर्ण ढंग से अवगत करा दिया गया है।

पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं, और इस वर्ष बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पारस्परिक कार्यकलापों में भी अच्छी प्रगति हुई है। केवल पाकिस्तान के मामले में उसके द्वारा जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद और विद्रोह का समर्थन किये जाने तथा विश्व भर में भारत-विरोधी कार्य किये जाने के कारण संबंधों को सामान्य बनाने के हमारे प्रयासों को गहरा धक्का लगा है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के समक्ष शिमला समझौते के अनुरूप एक अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध स्थापित करने के लिए बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। इस संबंध में द्विपक्षीय वार्ता की गई, किन्तु पाकिस्तान के भारत विरोधी बयानों की भरमार से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारे और पाकिस्तान की जनता के बीच कोई झगड़ा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिये पाकिस्तान सरकार अपने नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर शिमला समझौते के

अनुरूप भारत-पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने की हमारी कामना में बराबर का सहयोग दे।

चीन के साथ हमारे संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सितम्बर, 1993 में प्रधानमंत्री की चीन यात्रा से और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शांति बनाये रखने के करार पर हस्ताक्षर करने से इन संबंधों में नये आयाम विकसित हुए हैं। इस करार के अधीन गठित विशेषज्ञ दल ने हाल ही में अपनी पहली बैठक की, और उसमें इस पेचीदा मुद्दे पर परस्पर संबंध स्थापित करने और उन्हें बनाये रखने की दोनों पक्षों की इच्छा को अभिव्यक्त किया।

भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को इसके चार्टर के उद्देश्यों के अनुरूप क्षेत्रीय सहयोग का माध्यम मानता है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष ढाका में हुये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ने आम हित के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे कि-गरीबी, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, महिलाओं, बालकों और युवाओं की स्थिति तथा मादक पदार्थों से संबंधित समस्याओं पर विचार किया। हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर के अनुरूप उसके सामाजिक-आर्थिक और अन्य उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से लेकर संस्कृति और खेलकूद के अनेक क्षेत्रों में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आपस में पारस्परिक रूप से जुड़े हुये हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आपसी समझबूझ की दिशा में, और ऐसे मुद्दों पर, जिनके संबंध में समझबूझ बढ़ाने की आवश्यकता है, मिलकर काम करना चाहते हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र के साथ व्यापक परीक्षण रोक संधि जैसे निरस्त्रीकरण से संबंधित

मसलों पर भी सहयोग किया है। हमारी आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के प्रति संयुक्त राज्य ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और पिछले दो वर्षों में संयुक्त राज्य ने भारत में काफी निवेश किया। इससे हमारे दोनों देशों के बीच जीवंत लोकातात्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष आदर्श परिलक्षित होते हैं।

विगत दिनों में हमारी मंत्री की समृद्ध परम्परा के आधार पर रूसी संघ के साथ हमारे संबंधों में आपसी समझ-बूझ और सहयोग बना रहा। दोनों देशों के समक्ष आई कुछ कठिनाइयों के बावजूद राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग का दोनों पक्षों द्वारा समर्थन करने का प्रयास किया गया। हमारे संबंधों को सुदृढ़ बनाने वाली हमारी सद्भावना और समझ-बूझ से आज के बदलते हुये परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में आगे सहयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने में हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिला है।

मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। 1993 में प्रधानमंत्री की उजबेकिस्तान और कजाकिस्तान की यात्रायें बहुत सफल रहीं। पिछले वर्ष उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी भारत की यात्रा की। भारत और इन दोनों देशों के बीच राजनीतिक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग तथा व्यापार, नागर विमानन और संस्कृति के क्षेत्रों में भी सहयोग के कई करारों पर हस्ताक्षर किये गये।

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ और पूर्वी एशियाई देशों के साथ बनिष्ठ सहयोग के एक नये युग के सूत्रपात के लिये संगठित रूप से प्रयास किया गया। नये आर्थिक संबंध स्थापित किये गये, और व्यापार बढ़ाया गया। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ के देशों के बीच क्षेत्रीय बातचीत का शुरु होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। अप्रैल, 1993 में प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा से भारत-थाई संबंधों को नया बल

मिला। भारत-सिंगापुर संबंधों में गुणात्मक सुधार हुआ है, और सिंगापुर के प्रधानमंत्री गोह चोक टोंग ने इस वर्ष जनवरी में हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा की। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो ने भी दिसम्बर, 1993 में भारत की यात्रा की। सितम्बर, 1993 में उप-राष्ट्रपति की वियतनाम यात्रा से वियतनाम के साथ हमारे संबंध सुदृढ़ हुये। सरकार जापान के साथ आर्थिक और अन्य संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिये सतत् प्रयास करती रही। कोरिया गणराज्य के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और गति प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 1993 में कोरिया गणराज्य की यात्रा की, जिसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही।

खाड़ी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध पारम्परिक रूप से सौहार्दपूर्ण रहे हैं, और अब आर्थिक सम्बन्धों में भी सहयोग बढ़ रहा है। सितम्बर, 1993 में प्रधानमंत्री की ओमान और ईरान की यात्राओं ने पारस्परिक आर्थिक लाभ के बढ़ते हुए सम्बन्धों की नींव डाली।

हम पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने तथा फिलिस्तीनी लोगों के जायज अधिकारों को वापस दिलाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम के रूप में इजरायल और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच सितम्बर, 1993 में सम्पन्न अंतरिम स्वशासी व्यवस्थाओं के सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत करते हैं।

भारत और यूरोपीय संघ ने विविध क्षेत्रों में आपसी लाभदायक सम्बन्धों को और अधिक विकसित करने को जो महत्व दिया है, उसका परिचय 20 दिसम्बर, 1993 को सम्पन्न साम्प्रदायी और विकास पर सहयोग समझौते तथा राजनीतिक बातचीत पर भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त बक्तव्य से मिलता है। पिछले वर्ष के दौरान यूरोप से जिन उच्च स्तर के गणमान्य व्यक्तियों ने भारत की यात्रा की, उनमें आयरलैंड

के राष्ट्रपति, स्वीडन के नरेश और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री सम्मिलित हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्विटजरलैंड में डावोस और जर्मनी की सफल यात्रायें कीं। डावोस में प्रधान-मंत्री ने विश्वभर से आए उद्योगपतियों, राजनीतिक नेताओं और प्रबुद्ध लोगों को संबोधित किया। इसके परिणामस्वरूप भारत की नीतियों और क्षमताओं के प्रति समझबूझ बढ़ी है। जर्मनी की यात्रा से द्विपक्षीय सम्बन्धों को और बल मिला है, तथा आर्थिक सहयोग और मजबूत हुआ है।

जुलाई, 1993 में मैंने तुर्की, उक्रेन और हंगरी की राजकीय यात्रायें कीं, जो इन देशों के साथ हमारे सहयोगपूर्ण सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने की हमारी इच्छा का परिचायक है।

इस वर्ष के दौरान हमने उप-सहारा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापक पारस्परिक बातचीत की, जिसमें बुरुफिनो फासो, मारीशस, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्तर की यात्रायें शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका में हो रही विकास की सकारात्मक गतिविधियाँ हमारे ध्यान में हैं, और वहाँ पर बहुमत वाली सरकार शीघ्र स्थापित हो, इसकी हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

भारत राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मामलों, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, मानवाधिकार, पर्यावरण और जनसंख्या से संबंधित विषयों पर विश्व कार्यसूची को एक स्वरूप प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट-निरपेक्ष आंदोलन अथवा इन विषयों से संबंधित अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की विभिन्न बैठकों में विश्व सहमति को बढ़ावा देने के लिए हमने विकासशील देशों को विशिष्ट चिन्ताओं को उजागर करने में बढ़-चढ़ कर भाग लिया है।

वर्ष 1993 आर्थिक सुधारों के लाभों और सरकार द्वारा की गई राजनीतिक पहल को सुदृढ़ करने का वर्ष रहा। हमने सन् 1994 में इस आशावाद के साथ प्रवेश किया है कि हम अपने आर्थिक विकास की गति को और अधिक बढ़ायेंगे। लोगों ने सुधारों के पक्ष में और साम्प्रदायिकता

के विरुद्ध जो समर्थन दिया है उससे हमारा यह आशावाद सुदृढ़ हुआ है।

मुझे विश्वास है कि इस सत्र के दौरान तथा उससे आगे भी आपकी बहस तथा विचार-विमर्श लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में राष्ट्र को और आगे ले जाएगी। मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप अपने कार्य में जुट जायें। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

जयहिन्द

[*Text of the President's Address in English*]

Hon'ble Members,

I welcome you to this session of Parliament.

As I address you in the new year, I sense that the country is today in a frame of mind different from the one it was in, this time last year. We faced many difficulties at the beginning of the year 1993 but our people displayed tremendous resilience as the year progressed and 1993 ended certainly on a note of optimism. There was steady progress on all fronts as evidenced from the improved law and order situation, a record foodgrains production, unprecedented levels of procurement, very high levels of foodgrains stocks, containment of the rate of inflation at a single digit level comfortable, foreign exchange reserves, considerable reduction in trade gap, buoyancy in exports, improved performance in certain essential areas of the infrastructure sector, and increased inflow of foreign investment both direct and portfolio. All these have symbolised and justified this emerging optimism. Clearly, we have regained our elan internally and our confidence globally. We have reason and justification to feel encouraged at the all round performance. But we still have a long way to go before we achieve the objectives we have for ourselves in social and economic development. It is on this note of cautious optimism that Government approaches its tasks in 1994.

There has been overall improvement in the law and order situation. The situation in regard to insurgency in the North-East has shown improvement. The gains of last year in Punjab were consolidated. The elections to the Assemblies in five States and the National Capital Territory of Delhi were peaceful. Government is determined to consolidate the gains of this improvement and address the areas of concern that still remain.

Around this time last year the Ayodhya issue had cast its long shadow on the national scene. There was a great deal of concern over the possible fall-out of the demolition and the riots that followed. Thanks to the inherent wisdom and sagacity of the Indian people, the grim predictions that were being made have been proved wrong. The atmosphere has improved considerably and we can hope for a lasting solution to the dispute. Proceedings are continuing in the Supreme Court on the reference made to it under the Constitution. Government will take appropriate measures in the light of the opinion of the Supreme Court.

The Ayodhya issue is the most convincing demonstration in recent times of the danger inherent in mixing communalism and politics. It is of utmost importance to correct this aberration and keep both religion and politics in their legitimate domains. Our secular State demands nothing less. The issue needs to be debated fully and effective measures evolved. The Government will welcome suggestions in this regard.

In Jammu and Kashmir we pursue our policy of firm action against terrorism. The police and the security forces have gained considerable success during the year in their counter-terrorist operations. Steps have been taken to further improve their operational efficiency. Every effort is made to

see that the maximum restraint is exercised in the use of force. The grave crisis that arose in the Hazratbal shrine was handled by the administration and the security forces in a commendable manner, with the cooperation of the people. The resolution of this crisis demonstrated the efficacy of Government's approach of restraint. Whenever there has been any incident suggesting excessive use of force, an inquiry has been promptly instituted and action taken. Action against the terrorists is continuing in order to restore law and order. At the same time appropriate measures are being taken to tone up the administration. Development and economic activity have been intensified to generate employment opportunities. We are deeply concerned about the difficulties of the common people and the grievance redressal mechanism has been strengthened. We are also pursuing steps to bring about effective involvement of the people in dealing with matters which concern them. Jammu and Kashmir is an inalienable part of India and we shall foil any attempt to destabilise it either from across the border or from any other quarter.

In the North-East the setting up of the interim Bodoland Autonomous Council in pursuance of the Bodo Accord marks a positive step forward towards meeting the aspirations of the tribal population. Prompt action was taken by the Government of Assam in the districts of Kokrajhar and Bongaigaon when there was an outbreak of violence against the non-tribals. In Manipur Government : look action under article 356 of the Constitution following violence between Nagas and Kukis and general disruption of law and order. This demonstrated the Government's will to curb disruptive elements effectively.

The National Commission on Human Rights has been set up with a former Chief Justice of India as its chairman. Members of the Commission include a former Judge of the

Supreme Court and one former Chief Justice of a High Court. The setting up of the Commission is indicative of our continuing determination to deal with questions of human rights with promptitude and transparency. The Commission has started its work in right earnest.

In order to strengthen the accountability of the executive to Parliament, 17 Department-related Standing Committees of Parliament were constituted in April, 1993 to make detailed examination of Bills, Demands for Grants, Annual Reports of the Ministries and national basic long-term policy documents presented to the Houses. This will greatly facilitate the working of Parliament.

The country had its share of natural calamities. However, the unprecedented scale of damage in the Maharashtra earthquake stands out among these. In all these instances Government responded with commendable alertness and provided prompt relief. Governments of several other countries, the World Bank and other institutions promptly offered assistance and we are grateful to all of them. A massive reconstruction programme in the earthquake affected areas of Maharashtra is being taken up at an outlay of Rs. 1000 crores. Non-Governmental Organisations are being appropriately associated with the reconstruction programme.

The economic reforms introduced in 1991 gained momentum last year and have been pursued consistently. Still much more need to be done. Government is aware that the reform is an irreversible and continuous process and needs to be implemented with determination and foresight, keeping the responses and circumstances in the country constantly in view. As a result of this approach, the progress of implementation has been steady and firm and based on a general consensus. We shall hasten with care.

Based on the performance and prospects of the public and private sectors, the area of reservation of the public sector has been trimmed and some more industries have been delicensed. The new Exim Policy announced on the 31st of March, 1993, attempted the streamlining of procedures and the liberalisation of exports in agriculture and services, where the country has a comparative advantage. The Budget for 1993-94 provided fiscal incentives for investments in thrust areas.

In drawing up the reform package, stress has been laid by the Government on reforms in the financial sector. The financial institutions have necessarily to be restructured and strengthened to enable them to take on the new responsibility imposed by the expanded activity in the private sector. An important policy change was the unification of the exchange rate and the floating of the rupee in March, 1993. The fact that the rupee has remained steady since it was floated is testimony to the good judgement of the Government in the matter.

The basic economic indicators show that although the year started in a difficult environment the performance of the economy during 1993-94 has been satisfactory. In 1992-93, the Gross Domestic Product is estimated to have grown by 4%. In 1993-94, the Government expect the rate of growth to be maintained at about the same level. The inflation rate touched a low of below 6% for a short period during this year, the highest level being 8.4%

Global investors have shown growing confidence in the Indian market. Direct Foreign Investment approved since the inception of the new Industrial Policy till the end of 1993 is now approximately Rs. 13,000 crores in terms of equity. The total investment in these projects is estimated to be of the order of Rs. 65,000 crores. The significant point of this investment

is that the bulk of this, is proposed in sectors like power, oil refining, food processing, metallurgical industry, electrical equipment, chemicals, electronics and other priority areas. Only about 7% of the proposed investment will be for products which could be categorised as consumer goods. The investment inflow will be spread over a period of 3-4 years which is the gestation period of the mega projects.

Government continues to lay a great deal of emphasis on export promotion. The results of changes in the trade policy coupled with the floating of the exchange rate and the general liberalisation of the economy have yielded results and exports have shown good growth recording an increase of around 20% in dollar terms during April-December, 1993 compared to a little over 3% in the corresponding period in 1992.

Government attaches the highest priority to development of agriculture. The timely provision of adequate and reasonably priced inputs and the creation of a structure that provides for the timely announcement of prices which in turn promotes higher production so as to meet fully the domestic needs of the country as well as exports, are the major objectives of the Government. In keeping with the overall strategy, the Plan outlay for the Department of Agriculture and Cooperation has been raised by 26.6% from Rs. 1050 crores in 1992-93 to Rs 1330 crores in 1993-94. The production of foodgrains during 1992-93 was 180 million tonnes which was more than the production in 1991-92 by 7.1%. The Kharif foodgrains production in 1993-94 is expected to be 99 million tonnes. The prospects for Rabi are excellent.

Government is encouraging diversification of the agriculture sector through emphasis on horticulture, aquaculture, oilseeds, pulses and other commodities which have an export potential. This would be done without detriment to the interests of our

own consumers. Steps are being taken to revitalise the rural cooperative credit system as also marketing, processing and other services essential to the farmers, particularly in the far-flung areas. Extension services would be broad-based keeping in view the new priorities in agriculture including through greater involvement of the voluntary organisations.

As a measure of reducing poverty levels, our agricultural strategy would aim at increasing agricultural production in the rainfed areas through an integrated strategy of soil and water conservation and increased use of agricultural inputs such as organics and bio-fertilisers and improved technology. During the 8th Plan Rs. 1100 crores have been allocated for the restructured National Watershed Development Project for rainfed areas. About 30 lakh hectares of land would be treated for sustainable production of food, fodder, fuel and fibre through dry land farming technology. Household production systems would diversify as a consequence and ultimately the income levels and employment opportunities for the watershed community would improve. The project would also enhance availability of ground water resulting in drought proofing of the project areas. 2500 micro watersheds have been identified in rainfed areas for development and work on these has started.

The manufacturing capacity of nitrogenous fertilisers has been increased and more is being planned. The availability of raw materials required for fertiliser production within the country being limited, efforts are being made to set up joint ventures abroad, particularly in the Gulf and West Asia. Government will continue to take all measures required to bring about a balanced application of soil nutrients so that production levels are sustained.

As part of the Agriculture Policy States have been advised to remove all intra and inter-state restrictions on the movement of foodgrains.

Government's commitment to

safeguard the interests of the consumer remains as strong as ever. The Central issue price for the Revamped Public Distribution System areas continues to be kept at a price lower

by Rs. 500 per metric tonne compared to the prices in the general Public Distribution System, to enhance affordability by the poor. At the inception of the scheme in 1992, 10,580 new fair price shops were estimated as required to be opened in the Revamped Public Distribution System areas to strengthen the delivery system. Against this 11,681 new fair price shops have been opened in these areas, going beyond the target. New storage space of 1,81,296 tonnes has also been created or hired since the inception of the scheme. A midterm review of the Revamped Public Distribution System has revealed that nearly 1.5 million tonnes more of food grains went to the rural areas than before the inception of the scheme, thus adding a new rural dimension to the public distribution system. With a record food stock holding of 22 million tonnes in the central pool reached on 1st January, 1994, resulting from stepped up procurement efforts. Government is comfortably placed to augment the coverage further in these areas, should it become necessary

It is Government's determination that no vulnerable section of the population—be it women, children, minorities, scheduled castes, scheduled tribes or backward classes—should remain outside the mainstream of development. In all areas of development of the poor, resource allocations were enhanced during 1993-94 compared to the previous year. The revised outlay for the Ministry of Rural Development went up by 56 per cent while the plan outlay of the Welfare Ministry was raised from Rs. 820 crores to Rs. 980 crores. The Jawahar Rozgar Yojana has been strengthened in 120 most backward districts. The subsidies under the Integrated Rural Development Programme were enhanced by Rs. 1000 per household. The improved Tool Kits to Rural

Artisans programme started in 1992-93 was extended in 1993-94 to 100 more districts, thus covering in all 162 districts in the country benefiting 2,30,000 rural artisans. Comprehensive programmes for the welfare and development of the Weavers were evolved. They include housing, work sheds, handloom development centres, and quality dyeing units, training in improved practices and provision of working capital. These programmes with a total outlay of Rs. 1372 crores were started during the year. The scheme for Handloom Development Centres and Quality Dyeing Units launched towards the end of 1993 seeks to merge and expand existing units and establish new ones. Against the 1993 target of 120 Centres and 20 Units, 213 Centres and 94 Units have been approved. 25 Centres and 25 Units have already started operating.

Government has formulated three new and innovative schemes to benefit the poor, particularly rural women and urban youth.

The Employment Assurance Scheme introduced in 1,752 of the most backward and remote blocks of the country, where seventeen crores of the country's poor people live, will provide assured wage employment for 100 days during the lean agricultural season to the rural labour. This scheme thus expands rural employment to fuller levels.

The Mahila Samridhi Yojana will empower rural women by enabling them to gain and exercise control over their own earnings and household resources. Already, more than 4 lakh women have opened accounts under this scheme in rural post offices. This scheme, along with the Rashtriya Mahila Kosh, would greatly enhance opportunities for self-employment among rural women.

To provide sustained employment to the educated urban youth in micro enterprises, a Rozgar Yojana has been launched. About 1,95,000 applications have been processed and recommended to banks and about 2,000 of them have also been sanctioned. During the current year, the scheme will cover 40,000 beneficiaries and from 1994-95 onwards it is intended to cover 2.20 lakh beneficiaries every year, thus, covering in all 7 lakh beneficiaries during the rest of the 8th Plan period. The Reserve Bank of India has been instructed to support the programme fully. The scheme provides for 22.5 per cent reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and 27 per cent for the Other Backward Classes with preference for women.

A significant role has been envisaged for Non-Government Organisations in all these programmes to generate awareness and for their effective implementation.

To monitor the progress of implementation of the programmes of the weaker sections and to provide the direction and thrust required, the Prime Minister has set up a Special Cell in the Prime Minister's Office. This Special Cell will receive feedback from the implementing Departments and also information based on field visits and independent evaluations so as to remove all possible bottlenecks in the programmes. A Special Committee of Secretaries responsible for the implementation of these three programmes has also been set up to supervise the coordinated implementation of these programmes in the field.

Communication facilities will be further extended in rural areas. In 1993-94, 46,800 Panchayats will be connected by telephone. It is proposed to provide public telephone-to 72,000 villages during 1994-95.

In the schemes for the welfare of Scheduled Castes, the allocation under Special Central Assistance for the Special Component Plan was augmented in 1993 and its scope expanded to include schemes for infrastructure development in areas with fifty per cent or more Scheduled Caste population.

An important landmark of the year was the passing of the National Commission for Safai Karamcharis Act which would help the rapid implementation of the liberation and rehabilitation of the safai karam-charis. The National Commission is being constituted.

Government is fully alive to the situation arising from atrocities against the Scheduled Castes in certain parts of the country. Protection to the Scheduled Castes under the law as well as the effective implementation of programmes of socio-economic development meant for them would be ensured. During 1992-93, nearly 21 lakh Scheduled Caste families and 8 lakh Scheduled Tribe families were assisted to cross the poverty line under the 20 point Programme. During 1993-94 the number of assisted families is likely to reach 27 lakh Scheduled Caste families and 9 lakh Scheduled Tribe families.

A scheme of Educational Complexes in areas where tribal female literacy is very low was initiated during the year. 13 such Complexes have so far been sanctioned. The turn over of the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India rose from Rs. 22 crores in 1991-92 to Rs. 86 crores in 1992-93. This is expected to be much higher in the current year.

The National Backward Classes Finance and Development Corporation made significant advances during the current year. During 1993 it sanctioned Rs. 80 crores as loans. In the coming year it proposes to double its operations.

The long awaited reservation of vacancies for Other Backward Classes in the services under the Government of India became a reality on 8th September, 1993 when the present Government issued orders for 27% reservation for Other Backward Classes. With this, one of the most important aspirations of the Other Backward Classes of the country has been met.

The work relating to the publication of the works of Baba Saheb Ambedkar in regional languages was taken forward and two volumes each were brought out in Hindi, Tamil and Gujarati, with the work in the other languages proceeding well. Eight Chairs have been sanctioned in different Universities for undertaking research in the philosophy of Baba Saheb.

A new Wakf Bill 1993 has been introduced in Parliament in August, 1993 replacing the existing Wakf Act, 1954 and the Wakf (Amendment) Act, 1984. This Bill, *inter-alia*, provides for a more democratic composition of the Wakf Board with provision of Wakf Tribunals to decide issues relating to Wakf matters and for better protection and management of Wakf properties. A National Minorities Finance and Development Corporation will become operational this year with an authorised share capital of Rs. 500 crores for promoting the economic development of the minorities. The modalities are being worked out.

In my last address to you I had referred to the review of the 1986 National Policy on Education undertaken in 1992 and the modifications effected. Government continues to give very high priority to literacy and primary education based on the innovative strategies of Total Literacy Campaigns backed by Post Literacy Campaigns and a new district-specific and community oriented approach to primary education. All the 18 districts of Kerala

and Pondicherry have achieved total literacy. In the 32 districts which have already successfully concluded the Total Literacy Campaigns. Post Literacy Campaigns have been launched to ensure that the neo-literates do not lapse into illiteracy. At present 238 Total Literacy Campaigns are going on in 258 districts.

The new District Primary Education Programme lays emphasis on participatory planning and management and focuses on the education of girls. It seeks to enhance school effectiveness through inputs in teachers training and decentralised management. India played host recently to the Education for All summit of the nine high population countries of the world when our commitment as well as that of the international community to achieving Education for All by the turn of the century was reaffirmed. On this occasion the Prime Minister announced Government's decision to raise the outlay on education to 6% of the GDP by the turn of the century. This will be kept in view while formulating the Ninth Five Year Plan. Further,¹ through disaggregated target setting and decentralised management Government aims to achieve its objective of Education for All.

On account of sustained efforts of the Government of India and the State Governments in the implementation of the National Family Planning Programme, the annual rate of growth of population is showing a declining trend. The annual average exponential rate of growth in 1981-91 was 2.14%. The annual rate of increase has come down to 1.9% in 1992. The Crude Birth Rate which was 41.7 per thousand in 1951-61 has come down to 29 per thousand in 1992. The Crude Death Rate which was 22.8 in 1951-61 has come down to 10 in 1992. The total Fertility Rate which was 5.97 in 1951-61 has come down to 3.6 in

1991. The Infant Mortality Rate for the country as a whole has come down from 146 per thousand live births in 1961 to 79 in 1992. While these are significant achievements, yet the increase in numbers is staggering. Government attaches the highest importance to the reduction in the rate of growth of population. There is a national consensus to promote Family Welfare. Multi-dimensional and multi-sectoral efforts involving State Governments, opinion leaders, Non-governmental Organisations and all sections of the society are essential. All political parties must unanimously exhort the people to adopt the small family norm and transform the-family planning programme into a mass movement. The National Development Council (NDG) has endorsed the recommendations of the Committee on population set up by it earlier. The NDC also decided that wider consultations should take place on the future course of action needed for the implementation of the recommendations of the NDC Committee with Chief Ministers and opinion makers. This will be done shortly.

We are aware of the linkages between the development process and the protection of the environment. The need for the conservation and wise use of natural resources is reflected in our major river cleaning and pollution abatement programmes, as in our forest and wildlife policies. While participating in the continuing international debate on biodiversity, climate change and desertification, we have kept in focus the basic issue raised in the Rio Summit of 1992 of access to resources and technology. Within the Government, our development efforts will take full note of all our environmental concerns.

The Space programmes have made steady progress. We had a failure in the flight of the Polar Satellite Launch Vehicle, but this has been put to good use. The Data collected has been analysed and it has proven

the effectiveness of complex systems involved. The next flight of the Polar Satellite Launch Vehicle is planned for August-September, 1994. There has also been progress in the development of the Indian Geo-Syn-chronous Satellite Launch Vehicle, which would enable launch of INSAT class of satellites some years hence. The successful launch and commissioning of INSAT-2B last year, within a year of commissioning INSAT-2A, is a demonstration of our capabilities. INSAT-2B has enabled Doordarshan to augment its services with five satellite channels. This has strengthened the programmes telecast by Doordarshan in regional languages.

India has a strong and large scientific and industrial infrastructure. It also has demonstrated capability in several high technology fields. In this context I am sure Honorable Members will join me in applauding the successful demonstration of high technology in the launch of 'Agni' last Saturday. The pace of technological changes and the need to shift to technologies which are environment-compatible impose upon us various demands. Restrictions being placed on transfer of technology require us to rely even more on our own talents. Government is determined to give every encouragement for this to happen by tapping the great potential that the country possesses. In the context of the emerging economic scenario the benefits of research will be harnessed for use by industry. A fillip will be given to exports of high technology products. The thrust will be on information technologies and genetic engineering and biotechnology. Advanced materialist and devices for use of solar and other non-conventional energy sources will also be priority areas.

Our Armed Forces maintain their constant vigil on our borders to safeguard the territorial integrity of our country. The nation is proud of them; and of the defence scientists and engineers who have contributed commendably to ou

defence preparedness. Progress in the indigenous development of arms and ammunition and the diversification of the defence production units is proceeding apace.

In addition to their normal duties, the armed forces have been assisting the civil authorities in maintaining law and order, whenever required and in counter-insurgency operations. They have also been helping in rescue and relief operations in times of natural disasters. Their performance in these areas has been exemplary. Government remains committed to providing better facilities and conditions to serving and retired armed forces personnel. Those posted in field areas have recently been granted higher allowances. It has been decided to extend the benefit of the one-time increase scheme in pensions to an additional two lakh pensioners.

As a result of sustained international marketing, Government has succeeded in instilling confidence in the international community that India is among the safest tourism destinations of the world. This has resulted in an all time record of arrival of tourists in the months of December, 1993 and January, 1994 registering an increase of 23.8% and 28.4% respectively over the corresponding months in 1992 and 1993-

The foreign policy of the Government focussed during the last one year on securing our economic interests in our relations with countries abroad while continuing to promote our political and security interests. The significance of our economic reforms was effectively conveyed abroad-

Our relations with our neighbours continued to be cordial, and our interaction in various fields with Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal and Sri Lanka recorded good progress-during the year. In the case of Pakistan, however, its continuing support for terrorism and sub-

version in J&K and anti-Indian activities world-wide seriously hampered our efforts at normalising relations. The Prime Minister offered Pakistan a dialogue aimed at establishing good-neighbourly relations as enshrined in the Shimla Agreement. Bilateral talks have since taken place, but the stridency of Pakistan's anti-Indian statements has grown, adversely affecting at improving bilateral ties. There are no quarrels between us and the people of Pakistan. We feel that for good relations between our countries the Government of Pakistan should give up its negative approach and reciprocate our desire to normalise India-Pakistan relations in accordance with the Shimla Agreement.

Our relations with China have improved markedly. The Prime Minister's visit to China in September 1993, and the signing of the Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control have brought them to a new stage of development. The Expert Group set up under this Agreement held its first meeting recently, reflecting the desire of both sides to maintain and continue the interaction on this complex issue.

India values SAARC as an instrument of regional cooperation consistent with the objectives of its Charter. The Prime Minister attended the SAARC Summit in Dhaka last year. SAARC has recorded progress in dealing with certain important issues of common interest such as poverty, terrorism, population growth, problems relating to the status of women, children, youth and drugs and psychotropic substances. We continue to play an active role in SAARC with a view to promoting its socio-economic and other objectives in accordance with the SAARC Charter.

Our interaction with the United States has traditionally ranged over

a number of areas from Education and Science and Technology to Culture and Sports. We have also co-operated in the UN on issues relating to disarmament such as the comprehensive test ban treaty. The response from the United States to our economic liberalisation policies has been very positive and the US investments in India in the last two years were very substantial. We look forward to working with the United States towards mutual understanding, including on those issues on which such understanding needs enhancement. This will reflect the vibrant democratic and secular ideals of our two countries.

Relations with the Russian Federation, drawing upon the rich traditions of our friendship of the past, continued with mutual understanding and cooperation. Despite certain difficulties the two countries face, cooperation in the political, economic, commercial and other areas was sought to be promoted by both sides. The goodwill and understanding that underpins our relations reinforce our joint efforts at identifying possibilities of further cooperation in various areas in today's changed context.

Special attention was given to strengthening relations with the Central Asian region. The Prime Minister paid very successful visits to Uzbekistan and Kazakhstan in 1993. The Uzbek and Kazakh Presidents also visited India during the past year. A number of accords have been signed between India and these two countries in fields ranging from political cooperation and cooperation in science and technology to trade, civil aviation and culture.

A concerted effort was made to forge a new era of closer cooperation with ASEAN and East Asian countries. New economic linkages were established and trade increased. The commencement of a sectoral dialogue between India and the ASEAN was a notable development. The Prime Minister's visit to Thailand in April,

1993 gave a new impetus to Indo-Thai relations. India-Singapore relations were qualitatively upgraded and Prime Minister Goh Chok Tong of Singapore visited India as Chief Guest at our Republic Day celebrations in January this year. Prime Minister Mahathir Mohamad of Malaysia and President Soeharto of Indonesia also visited India in December, 1993. Our ties with Vietnam were reinforced with the visit of the Vice-President to Vietnam in September, 1993. The Government continued to make sustained efforts to further enhance economic and other linkages with Japan. The Prime Minister's visit to the Republic of Korea in September, 1993, with a view to lending further momentum to bilateral economic ties with that country, received a positive response.

Our relations with the Gulf countries, traditionally cordial, are now marked by increasing economic interaction. The Prime Minister's visits to Oman and Iran in September, 1993 laid the foundations of an expanding relationship for mutual economic benefit.

We welcome the signing of the Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements between Israel and the PLO in September 1993, as notable step towards peace and stability in West Asia and the restoration of the legitimate rights of the Palestinian people.

The importance attached by India and the European Union to further developing mutually beneficial relation in diverse fields was symbolised by a Cooperation Agreement on Partnership and Development concluded on December, 20, 1993 and the Indo-EU Joint Statement on Political Dialogue. High level dignitaries who visited India from Europe during the past year included the President of Ireland, the King of Sweden and the Prime Minister of the Netherlands. The Prime Minister recently paid a very successful visit to Davos in Switzerland and to Germany At Davos the Prime Minister address-

ed a worldwide audience of industrialists, political leaders and academicians. As a result, the appreciation of India's policies and potential has grown. The visit to Germany has given a further impetus to bilateral ties and has strengthened economic cooperation.

The state visits which I undertook to Ukraine, Turkey and Hungary in July, 1993 were a manifestation of our desire to consolidate our cooperative with these countries.

During the year we had wide interaction with countries in sub-Saharan Africa including visits at the level of President and Prime Minister from Burkina Faso, Mauritius, Tanzania, Gambia and Zimbabwe. We have noted the positive developments in South Africa and look forward to the early establishment of majority rule there.

India continues to play an active role in shaping the global agenda on issues pertaining to political and security matters, economic and social development, human rights, environment and population. In the various meetings of the United Nations, the Non-aligned Movement or other international bodies on these issues, we have taken a lead in articulating the specific concerns of the developing countries with a view to promoting a global consensus.

1993 was a year of consolidating the gains of the economic reforms and political initiatives of the Government. We entered 1994 with the optimism of accelerating our pace of economic growth, strengthened by a reassuring verdict of the people in favour of reforms and against the forces of communalism.

I am confident your debates and deliberations in the course of this session and beyond will take the

nation forward in fulfilling the aspirations of the people. I commend you to your tasks and wish you all success.

JAI HIND

OBITUARY REFERENCES

MR. CHAIRMAN : Hon'ble Members, I refer with profound sorrow to the passing away of Shrimati Maya Devi Chetty, Shrimati Seeta Yudhvīr and Shri Bhim Raj, former Members of Rajya Sabha.

Shrimati Maya Devi Chetty was born in March, 1921 in Nepal. She passed away on the 20th December, 1993 at Darjeeling. She was actively associated with Bharat Scouts and Guides in different capacities. Shrimati Maya Devi was an ardent social worker and was associated with several social welfare organisations connected with the uplift and welfare of women.

She was a Member of Rajya Sabha representing the State of West Bengal from April, 1952 to April, 1958 and again from April, 1958 to April, 1964. She served on the House Committee and was on the Panel of Vice Chairmen, Rajya Sabha in 1959.

Shrimati Seeta Yudhvīr passed away on the 10th January, 1994. Shrimati Yudhvīr was born in November, 1922 at Dar-es-Salaam in East Africa. She had her education at Baroda.

Leading a simple life devoted to service of the under-privileged, Shrimati Yudhvīr actively worked for the cause of integrated State of Andhra Pradesh when separate Telangana agitation was launched.

A dedicated social worker, Shrimati Yudhvīr was District Guides Commissioner, Hindustan

Scout Association Lahore in 1946-47. She was associated with women's welfare organisations. She was also the Chief Editor of Hindi *Milap*.

Shrimati Yudhvīr was a Member of the Rajya Sabha representing the State of Andhra Pradesh from April, 1958 to April, 1964 and again from April, 1964 to April, 1970. She was a Member of the Indian Delegation for Inter-Parliamentary Union Conference at Copenhagen, Denmark in 1964.

Shri Bhim Raj passed away on the 15th February, 1994 at New Delhi after brief illness. Born in December, 1943 at Ganga Nagar, Rajasthan, Shri Bhim Raj had his education at Chandigarh.

An agriculturist by vocation, Shri Bhim Raj started his political career as Sarpanch at the age of 21 and continued there for more than a decade. He commenced his legislative career after election to the Rajasthan Legislative Assembly in 1972.

Shri Bhim Raj was a Member of the Rajya Sabha representing the State of Rajasthan from April, 1978 to April, 1984 and again from April, 1984 to April, 1990. He was also the Chairman of the House Committee of Rajya Sabha from 1986 to 1988.

We deeply mourn the passing away of Shrimati Maya Devi Chetty, Shrimati Seeta Yudhvīr and Shri Bhim Raj.

I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.

(Hon. Members then stood in silence for one minute)

MR. CHAIRMAN : Secretary General, will convey to the mem-